

Daily Current Affairs

Date : 30 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति - 2026
2.	CBI द्वारा विकसित ABHAY चैटबॉट के संबंध में एडवाइजरी
3.	राजस्थान के 06 केन्द्रों पर ऑन-डिमांड परीक्षा का संचालन
4.	चर्चा में जैसलमेर का 'डांडेवाला गैस क्षेत्र'
5.	RSCIT पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. नींदड बैनाड़ बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट ईको ट्रेल 2. सुरता देवी सैनी : 'सेवा से समृद्धि' क्षेत्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय सम्मान 3. दो कुलगुरुओं को अतिरिक्त कार्यभार 4. अवधेश आकोदिया को पहला 'नारायण बारेठ पत्रकारिता पुरस्कार' 5. महाराणा : द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर 6. देश का पहला रेलवे बायोटॉयलेट बैक्टीरिया निर्माता कारखाना 7. नीरज चौधरी : अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस - 2026 पर सम्मानित
7.	कलाई-II परियोजना एवं व्हाइट-बेलिड हेरॉन
8.	न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या
9.	विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)
10.	दहेज मृत्यु सामाजिक संकट का रूप में
11.	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA)
12.	अब्राहम समझौता
13.	लोकायन 26 अभियान
14.	वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन 2026-2035 रिपोर्ट

-:1:-



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति - 2026



चर्चा में क्यों?

- RIICO द्वारा 01 जून, 2026 से प्राइवेट डवलपर्स के माध्यम से औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए।

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026

- मॉडल 'ए' और 'डी' के तहत पार्क विकसित करने के लिए, रीको ने मांगे आवेदन
- 9 स्थानों पर, 645 हेक्टेयर में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी
- निजी डेवलपर्स के माध्यम से विकसित होंगे पार्क, आवेदन 1 जून से



--2--

Daily Current Affairs

Date : 30 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि RIICO द्वारा 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति - 2026' के मॉडल 'A' और 'D' के तहत राज्य के 9 जिलों में 645 हेक्टेयर भूमि में नए पार्क विकसित किए जाएंगे।

चयनित स्थान :

मॉडल	स्थान (ज़िला)	विवरण
मॉडल 'A'	वेदरलाई (बालोतरा) बिजौली (धौलपुर) नरबदिया (चित्तौड़गढ़) कोड़िया (भीलवाड़ा) गूढ़ा आशिकपुरा और नूरपुर राजाहेड़ा (दौसा) मायेजा (बूँदी) भाकरी मोलास (डीडवाना-कुचामन)	मॉडल 'A' के तहत रीको द्वारा आवंटित लगभग 374 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर निजी डवलपर्स द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा।
मॉडल 'D'	कनई कलां (अजमेर) कोटवालों का बास, नांगल झामरवाड़ा, रालतवाता और सुधरामपाड़ा (दौसा)	मॉडल 'D' के तहत पीपीपी मोड पर कुल 271 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति - 2026
- मंत्रिमण्डलीय अनुमोदन : 25 फरवरी, 2026 को।
- नीति का अनावरण : 18 मार्च, 2026 को।
- नीति का उद्देश्य : प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, भूमि-जल-ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास।

-:3:-

Daily Current Affairs

Date : 30 May, 2026



- प्रस्तावित नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार मॉडल निर्धारित किए गए हैं।
- **मॉडल - A** : रीको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डवलपर्स द्वारा विकास।
- **मॉडल - B** : 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर।
- **मॉडल - C** : संपूर्ण भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा।
- **मॉडल - D** : पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) द्वारा विकास।
- नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होंगी।
- **पूँजी अनुदान** : राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत श्रेणीवार पूँजीगत अनुदान देगी।
- **श्रेणी - I** : 100 एकड़ तक के पार्क हेतु अधिकतम ₹20 करोड़।
- **श्रेणी - II** : 100 से 250 एकड़ हेतु अधिकतम ₹30 करोड़।
- **श्रेणी - III** : 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिकतम ₹40 करोड़।
- **हरित विकास** : हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़/पार्क) का प्रावधान भी किया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RIICO)

- RIICO एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी स्थापना 28 मार्च, 1969 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम (RSIMDC) के रूप में की गई थी।
- 1 जनवरी, 1980 को इसे दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया:
 1. RIICO - राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
 2. RSMDC - राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम।

-:4:-

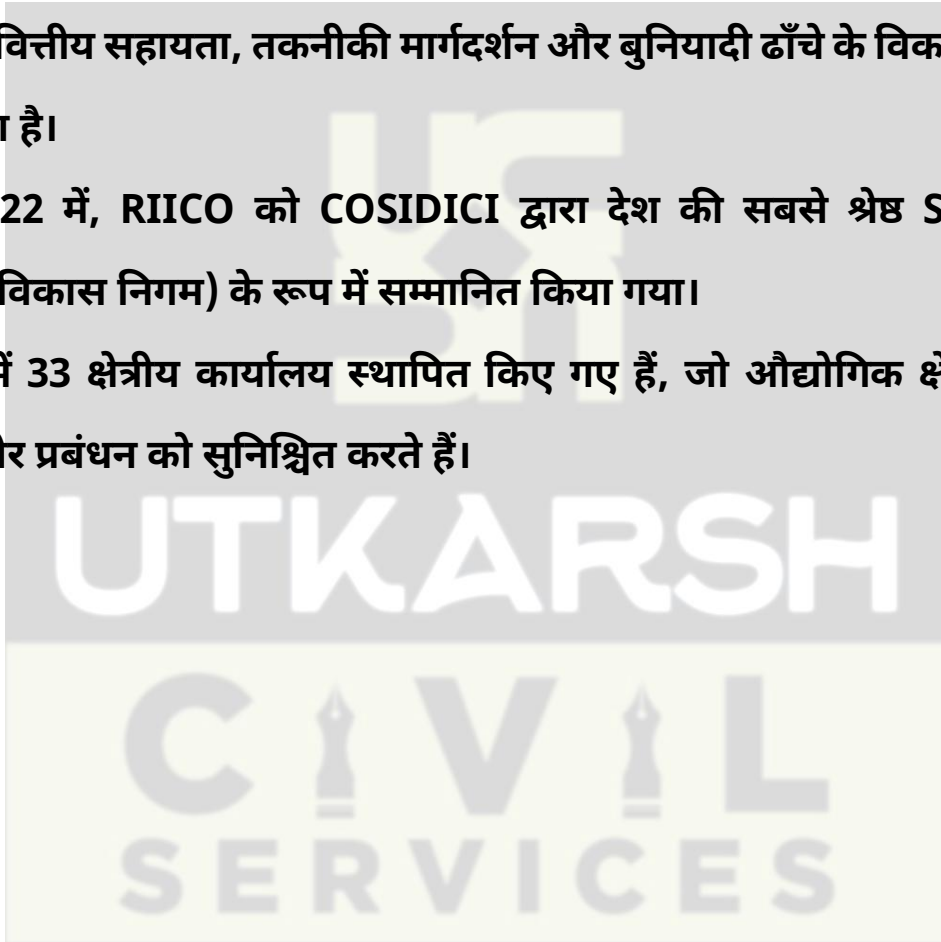
Daily Current Affairs

 Date : 30 May, 2026



मुख्य कार्य:

- यह राज्य के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करता है।
- एक वित्तीय संस्था के रूप में यह छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है।
- उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- वर्ष 2021-22 में, RIICO को COSIDICI द्वारा देश की सबसे श्रेष्ठ SIIDC (राज्य औद्योगिक विकास निगम) के रूप में सम्मानित किया गया।
- राज्य भर में 33 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं।



-:5:-

CBI द्वारा विकसित ABHAY चैटबॉट के संबंध में एडवाइजरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित AI आधारित चैटबॉट 'अभय' (ABHAY) के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई।

मुख्य बिन्दु:

- 'अभय' (ABHAY) : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर यू। (DIPR के अनुसार)
- ABHAY एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट है, जो इंटरनेट पर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध आम नागरिकों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा गार्ड की तरह कार्य करता है।
- यह चैटबॉट 24x7 लाइव रहता है, जो किसी भी व्यक्ति को मिले संदिग्ध नोटिस की वास्तविकता की तुरंत जाँच करता है।
- इस चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े फ्रॉड के दौरान नागरिकों को घबराहट में कोई भी गलत या आत्मघाती कदम उठाने से रोकना है।



ABHAY
AI - Based Helpbot for
Authentication of Your notices

अभय चैटबॉट की तकनीकी विशेषताएँ:

- **रीयल-टाइम अपडेट** : देश में जैसे ही साइबर अपराधी ठगी का कोई नया तरीका निकालते हैं, पुलिस और जाँच एजेंसियाँ इसके बैकएंड डेटाबेस को तुरंत अपडेट कर देती हैं, जिससे यह चैटबॉट नए फ्रॉड को भी पहचान लेता है।
- **नो-पैनिक गाइडेंस** : चैटबॉट को इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि यदि कोई डरा हुआ पीड़ित इससे बात करता है, तो यह उसे शांत रखकर स्टेप-बाय-स्टेप विधिक निर्देश देता है।
- **ऑटो-रूटिंग की सुविधा** : यदि मामला अत्यधिक गंभीर श्रेणी का होता है, तो यह यूजर को सीधे भारत सरकार के आधिकारिक शिकायत पोर्टल के लिंक पर रीडायरेक्ट कर देता है।
- **24x7 सेवा प्रदाता** : एक स्वचालित AI सिस्टम होने के कारण यह ठगी का शिकार होने वाले व्यक्ति को 24x7 विधिक सुरक्षात्मक जवाब देता है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **साइबर सुरक्षा में राजस्थान का स्थान** : ठगी गई राशि को फ्रीज करने और धोखाधड़ी नेटवर्क को तोड़ने के मामले में राजस्थान पुलिस देश में 5वें स्थान पर है।
- **राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना** : साइबर अपराध की नई चुनौतियों से बचाव के लिए राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना की जाएगी।
- **राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर ठगी की रोकथाम के लिए संचालित ऑपरेशन** : ऑपरेशन म्यूल अकाउंट एवं POS, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एंटी वायरस और ऑपरेशन वज्र प्रहार।
- **राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर** : 24 मई, 2025 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 'राजस्थान के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर' की शुरुआत की गई। यह साइबर सपोर्ट सेंटर 'रेस्पॉन्सिबल नेटिज़न्स एवं कोग्टा फाउंडेशन' द्वारा संचालित किया जा रहा है।

Daily Current Affairs



Date : 30 May, 2026



- **राजस्थान साइबर क्राइम कण्ट्रोल सेण्टर (R4C) :** प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की तर्ज पर 'राजस्थान साइबर क्राइम कण्ट्रोल सेण्टर (R4C)' की स्थापना की जाएगी।
- **सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर :** यह विश्वविद्यालय राज्य में साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के रूप में कार्य कर रहा है।



-:8:-



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

राजस्थान के 06 केन्द्रों पर ऑन-डिमांड परीक्षा का संचालन

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के तहत ऑन-डिमांड परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। छात्रों के शैक्षणिक वर्ष को बचाने और लचीली शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान में ऐसे 6 परीक्षा केंद्र संचालित हैं।



The poster features the NIOS logo with the motto 'विद्या सर्वत्र प्राप्यते' and the text 'On-demand Examinations are being conducted in Rajasthan'. It highlights that these exams are conducted under the National Institute of Open Schooling (NIOS). A central banner states: 'To save students' academic year and provide flexible education, six such examination centers are operational in Rajasthan.' To the right, five icons represent the benefits: Flexible Examination, Student Friendly, Save Academic Year, Accessible Education for All, and a handshake icon. The bottom of the poster shows a scenic view of a Rajasthan fort and states: 'NIOS is committed to providing quality, flexible and inclusive education to every learner across Rajasthan.'

मुख्य बिन्दु:

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, केंद्र सरकार द्वारा संचालित CBSE बोर्ड एवं विभिन्न राज्यों के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष है।

Daily Current Affairs



Date : 30 May, 2026



- इस संस्थान के द्वारा ऑन-डिमांड परीक्षा का संचालन किया जाता है, जो छात्रों को अपनी सुविधानुसार कभी भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के सुविधा देने के लिए बनाई गई है।
- इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाना, परीक्षा का तनाव कम करना और काम करने वाले युवाओं या खिलाड़ियों को लचीले तरीके से शिक्षा प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के तत्वावधान में वर्तमान में राजस्थान के 06 केन्द्रों पर ऑन-डिमांड परीक्षा का संचालन किया जा रहा है:-
 - केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 06, जयपुर।
 - केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 02, कोटा।
 - केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 03, बीकानेर।
 - केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 01, उदयपुर।
 - केंद्रीय विद्यालय, बूंदी।
 - केंद्रीय विद्यालय, सीकर।

-:10:-

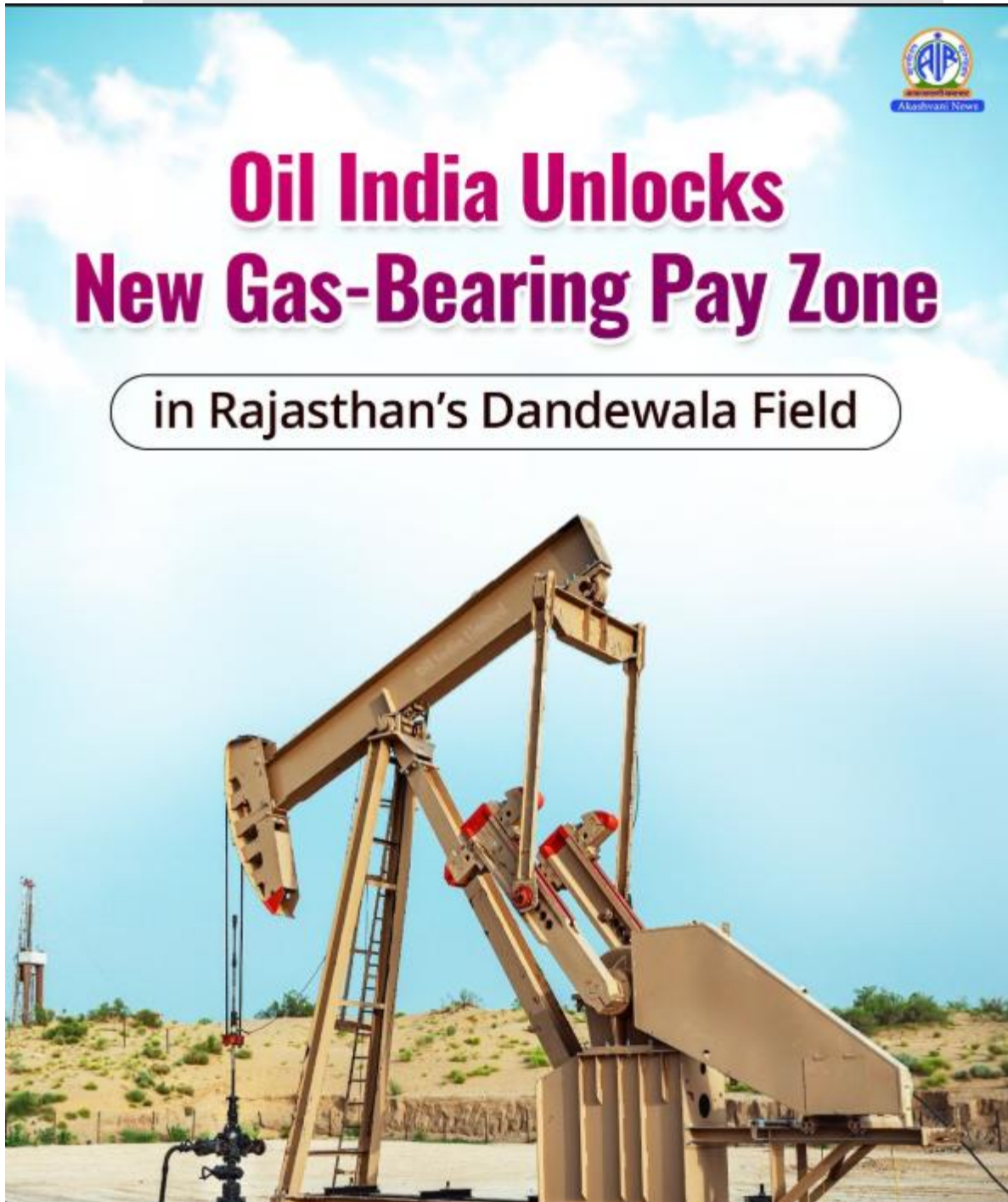


उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

चर्चा में जैसलमेर का 'डांडेवाला गैस क्षेत्र'

चर्चा में क्यों?

- ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने हाल ही में जैसलमेर जिले में स्थित डांडेवाला क्षेत्र में एक नए गैस युक्त पे ज़ोन की खोज की।



-:11:-

Daily Current Affairs



Date : 30 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- यह खोज उथले सानू फॉर्मेशन में की गई है, जहाँ से पहली बार प्राकृतिक गैस का सफल प्रवाह दर्ज हुआ है।
- गैस का यह नया स्रोत जमीन से लगभग 950 मीटर की गहराई पर मिला है।
- प्रारंभिक परीक्षणों के दौरान इस कुएँ से औसतन लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन (SCMD) प्राकृतिक गैस का प्रवाह दर्ज किया गया।
- प्रारंभिक भूगर्भीय अध्ययनों के अनुसार, इस नए क्षेत्र में लगभग 75 मिलियन मानक घन मीटर (MMSCM) गैस का भंडार होने का अनुमान है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:12:-



उत्कर्ष®

Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

RSCIT पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा RSCIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) कोर्स में विद्यार्थियों को कंप्यूटर साक्षरता के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग,
जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं के
लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का

निःशुल्क प्रशिक्षण

RS-CIT

आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण

RS-CFA

GST, Tally आधारित वित्तीय
लेखांकन प्रशिक्षण

RS-CSEP

स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी
डैवलपमेंट प्रशिक्षण

योजना के तहत आवेदन www.myrkcl.com/wcd पर किया जा सकता है।

मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RS-CIT) राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बुनियादी डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर कोर्स है।
- इस कोर्स को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा संचालित और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

- राजस्थान में कई सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए यह प्रमाण-पत्र एक अनिवार्य योग्यता माना जाता है।
- राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए समय-समय पर निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण योजना भी चलाई जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना:

- **उद्देश्य :** महिलाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- **प्रशिक्षण :** राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा।
- **पात्रता :** राजस्थान की वे महिलाएँ और लड़कियाँ जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिनके लिए सभी पाठ्यक्रमों में न्यूनतम आयु 18 वर्ष, RS-CSEP कोर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है और शेष पाठ्यक्रमों के लिए 40 वर्ष है।

योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम :

- महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)।
- महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एकाउंटिंग)।
- महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट (RS-CSEP)
- प्रशिक्षण।
- कौशल सामर्थ्य योजना।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	नींदड बैनाड़ बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट ईको ट्रेल - हाल ही में, मुख्यमंत्री ने जयपुर के नींदड वन क्षेत्र में 'नींदड बैनाड़ बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट ईको ट्रेल' का उद्घाटन किया। - नींदड-बेनाड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट ईको-ट्रेल एक महत्वाकांक्षी पर्यावरण पर्यटन (Eco-Tourism) और वन संरक्षण परियोजना है। - इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना और जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना है।
2.	सुरता देवी सैनी : 'सेवा से समृद्धि' क्षेत्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय सम्मान - असम के गुवाहाटी में आयोजित 'सेवा से समृद्धि : पंचायतों द्वारा सेवा प्रदायगी' क्षेत्रीय कार्यशाला में ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) सुरता देवी सैनी को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। - सुरता देवी सैनी राष्ट्रीय स्तर पर 6 कॉमन सर्विस सेंटर - विलेज लेवल एंटरप्रीन्योर (CSC VLE) में चयनित राजस्थान से एकमात्र प्रतिनिधि है। - संबंध : कोसाना, (पीपाड़, जोधपुर)। - भूमिका : राजस्थान ग्रामीण बैंक की बैंक बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट। - बैंक बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (BC) मॉडल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
3.	दो कुलगुरुओं को अतिरिक्त कार्यभार - प्रो. त्रिभुवन शर्मा (कुलगुरु, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार। - प्रो. एन. के. पाण्डेय (कुलगुरु, हरि देव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर) को विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जयपुर के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार।

4.

अवधेश आकोदिया को पहला 'नारायण बारेठ पत्रकारिता पुरस्कार'

- दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता अवधेश आकोदिया (जयपुर) को हाल ही में पहले 'नारायण बारेठ पत्रकारिता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- 'नारायण बारेठ स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार' वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त स्वर्गीय नारायण बारेठ की स्मृति में दिया जाता है।
- यह पुरस्कार ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब द्वारा प्रति वर्ष एक प्रतिभाशाली पत्रकार को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
- नोट : अप्रैल, 2026 में अवधेश आकोदिया (जयपुर) को राजस्थान में विधायक निधि (MLA-LAD) में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली रिपोर्टिंग के लिए 'दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवॉर्ड - 2026' से भी सम्मानित किया जा चुका है।

5.

महाराणा : द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर

- हाल ही में, उदयपुर में ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार ब्रायन मास्टर्स द्वारा लिखित पुस्तक 'महाराणा : द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर' का विमोचन किया गया।
- यह पुस्तक मेवाड़ राजवंश के गौरवशाली इतिहास, उनकी अद्वितीय परंपराओं और संप्रभुता को दर्शाती है। यह पुस्तक मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश पर आधारित है, जिसे 76 पीढ़ियों और लगभग 1500 वर्षों से अधिक पुराना और दुनिया का सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश माना जाता है।

6.	देश का पहला रेलवे बायोटॉयलेट बैक्टीरिया निर्माता कारखाना ■ अजमेर का कैरिज कारखाना देश में रेलवे का पहला बायोटॉयलेट बैक्टीरिया निर्माता कारखाना बना। ■ अजमेर में स्थित कैरिज एंड वेगन कारखाना उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) का एक प्रमुख तकनीकी केंद्र है। ■ बायो-टॉयलेट तकनीक : ट्रेनों के बायो-टॉयलेट में मल को पानी और गैस में बदलने के लिए इस विशेष एनारोबिक (बिना ऑक्सीजन के रहने वाले) इनोक्यूलम बैक्टीरिया का उपयोग होता है।
7.	नीरज चौधरी : अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस - 2026 पर सम्मानित ■ अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस - 2026 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में आयोजित समारोह के दौरान प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही और राजस्थान निर्वाचन आयोग के स्टेट स्वीप आइकॉन नीरज चौधरी को सम्मानित किया गया। ■ नीरज चौधरी के साथ-साथ भारत के दो अन्य पर्वतारोहियों- प्रेम सिंह (सेवानिवृत्त महानिरीक्षक, ITBP) और तुसी अनित शाह (थाले सागर चोटी फतह करने वाली पहली महिला) को भी सम्मानित किया गया।

SERVICES



भूगोल एवं भू-विज्ञान



कलाई-II परियोजना एवं व्हाइट-बेलिड हेरॉन

(स्रोत: INDIAN EXPRESS)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने व्हाइट-बेलिड हेरॉन के संरक्षण से जुड़ी चिंताओं के बीच कलाई-II जलविद्युत परियोजना को सैद्धांतिक वन मंजूरी प्रदान कर दी है।

मुख्य बिन्दु:

कलाई-II जलविद्युत परियोजना

- अवस्थिति: अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश।
- नदी: लोहित नदी (ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी)।

व्हाइट-बेलिड हेरॉन

- अन्य नाम: इम्पीरियल हेरॉन, ग्रेट व्हाइट-बेलिड हेरॉन।
- वर्तमान प्राप्ति क्षेत्र: इनका प्राप्ति क्षेत्र पूर्वी हिमालय के दक्षिणी गिरिपद तक सीमित है। ये मुख्य रूप से भूटान, पूर्वोत्तर भारत (असम और अरुणाचल प्रदेश) तथा उत्तरी म्यांमार में प्राप्त होते हैं।

संरक्षण स्थिति:

- IUCN लाल सूची: क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 में सूचीबद्ध।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या

(स्रोत: THE HINDU)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026' जारी किया। इस अध्यादेश का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करना है।
- 26 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद से यह 7वीं बार है, जब 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956' के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है।

मुख्य बिन्दु:

लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति (नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड)

- **उच्चतम न्यायालय:** लगभग 93,000 मामले लंबित हैं, जिनमें 22 मामले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, 5 मामले सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ और 2 मामले नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित हैं।
- **अधीनस्थ न्यायालय:** इनमें स्थिति और अधिक गंभीर है। उच्च न्यायालयों में 64 लाख से अधिक और जिला न्यायालयों में लगभग 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं।

न्यायालयों में लंबित मामलों के कारण:

- **संख्या बढ़ाने का सीमित प्रभाव:** पूर्व के अनुभवों (2008 और 2019) से पता चलता है कि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामले स्थायी रूप से कम नहीं होते, क्योंकि मामलों की जटिलता भी बढ़ रही है।
- **न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात की कमी:** भारत में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट ने 50 न्यायाधीशों का अनुपात बनाए रखने का सुझाव दिया था।
- **मूल दायित्व का कमजोर होना:** संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं को नियमित रूप से स्वीकार किए जाने के कारण उच्चतम न्यायालय अत्यधिक बोझ वाले अपीलीय न्यायालय में बदल गया है।
- **वित्तीय संसाधन:** भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.1% ही न्यायपालिका पर व्यय करता है।
- **वादी के रूप में सरकार:** लगभग 50% अभियोजनों के लिए सरकार जिम्मेदार है।
- **व्यवस्थागत कमियां:** मामलों की प्रारंभिक सुनवाई में प्रक्रियागत देरी, अवसंरचना में कमी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं विद्यमान हैं।

सरकारी पहलें:

- **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र:** न्यायालयों के बाहर लोक अदालत, मध्यस्थता, पंचाद आदि के माध्यम से मामलों को सुलझाकर न्यायालयों का बोझ कम किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय न्याय वितरण और विधिक सुधार मिशन (2011):** इसका उद्देश्य मामलों के निस्तारण में देरी और लंबित मामलों के बोझ को कम करना है।
- **अन्य पहलें:** न्यायपालिका की अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, आदि।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)

(स्रोत: THE HINDU)

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की कानूनी वैधता को बरकरार रखा।
- इसमें कहा गया है कि SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश को सुरक्षित करना है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव आधारित है वह सटीक और विश्वसनीय हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता का अंतिम निर्धारण नहीं है।
- ECI का यह दायित्व होगा कि वह इस मामले को नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्णय हेतु संदर्भित करे।
- यदि अंततः यह पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति नागरिक हैं, तो उनके नाम मतदाता सूची में बहाल किए जाने चाहिए।

मुख्य बिन्दु:

मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR)

- भारत का चुनाव आयोग, मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए सशक्त है।
- मतदाता सूची की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, आयोग प्रत्येक चुनाव से पहले या आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में संशोधन का आदेश देता है।

Daily Current Affairs



Date : 30 May, 2026



- ECI के 2025 के आदेश में SIR की घोषणा करते हुए इस प्रक्रिया के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं:
- 2003 में हुए गहन संशोधन के बाद से पिछले 20 वर्षों में तीव्र शहरीकरण और प्रवासन के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची में बार-बार, कई बार और दोषपूर्ण प्रविष्टियाँ हुई हैं।
- अनुच्छेद 326 के तहत आयोग का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिक ही शामिल हों।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र (या उसके भाग) के लिए मतदाता सूचियों का "विशेष संशोधन" करने का अधिकार है, जो नियमित संशोधन अनुसूचियों को रद्द कर देगा, बशर्ते कि कारण दर्ज किए जाएं।

-:22:-



समाजशास्त्र



दहेज मृत्यु सामाजिक संकट का रूप में

(स्रोत: THE WIRE)



चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'भारत में अपराध 2024' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण प्रतिदिन लगभग 16 महिलाओं की मौत हो जाती है।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार, 'दहेज से आशय कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु से है, जो विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के पश्चात विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या दी जाने के लिए करार की गई है।



मुख्य बिन्दु:

वर्तमान स्थिति (NCRB 2024 रिपोर्ट के अनुसार)

- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:** कुल 4,41,534 दर्ज मामलों में से 27.2% मामले 'पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता' के दर्ज किए गए।
- **दहेज मृत्यु:** लंबे समय में थोड़ी गिरावट के बावजूद, भारत में वर्ष 2024 में दहेज से जुड़ी 5,737 मौतें दर्ज की गईं।
- **सर्वाधिक मामले:** उत्तर प्रदेश (2,038) में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। इसके उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए।

संबंधित विधिक प्रावधान

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961:** दहेज लेने, देने या उसकी मांग करने को आपराधिक कृत्य बनाया गया है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS):

- **धारा 80:** दहेज मृत्यु के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है।
- **धारा 85:** पति या उसके नातेदारों द्वारा महिला के साथ की गई क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- **साक्ष्य:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 118 के तहत, आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए 'दोषी होने की धारणा' को आधार माना जाता है।
- **घरेलू हिंसा:** 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' महिलाओं को घर में होने वाली हिंसा से संरक्षण के लिए लागू किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के 2025 के निर्देश

- 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग' वाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
- **दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति:** इनकी नियुक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 अधिनियम के तहत सुनिश्चित की जाए।
- **अधिकारियों का प्रशिक्षण:** पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए।
- **लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण:** उच्च न्यायालयों से लंबित मामलों की संख्या की समीक्षा करने और उनका शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है।
- **अन्य निर्देश:** जिला प्रशासन द्वारा दहेज के खिलाफ जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए।

📦 योजनाएँ एवं नीतियाँ 📦

नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA)

(स्रोत: PIB)

📌 चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने NeSDA, 2025 पोर्टल प्रारंभ किया।

📌 मुख्य बिन्दु:

NeSDA 2025

- यह DARPG द्वारा तैयार किया गया द्विवार्षिक मूल्यांकन फ्रेमवर्क है।
- यह संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेमेंट सर्वेक्षण के ऑनलाइन सेवा सूचकांक पर आधारित है।
- **उद्देश्य:** नागरिकों के दृष्टिकोण से ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी तंत्र की प्रभावशीलता को मापना।
- **मापदंड:** यह राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों में ऑनलाइन सेवा प्रदायगी की उपलब्धता, सुलभता और परिपक्वता से जुड़े कई मापदंडों का मूल्यांकन करता है।
- **विस्तार:** यह प्रमुख क्षेत्रों में G2C (सरकार से नागरिक) और G2B (सरकार से व्यवसाय) सेवाओं को शामिल करता है।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



अब्राहम समझौता

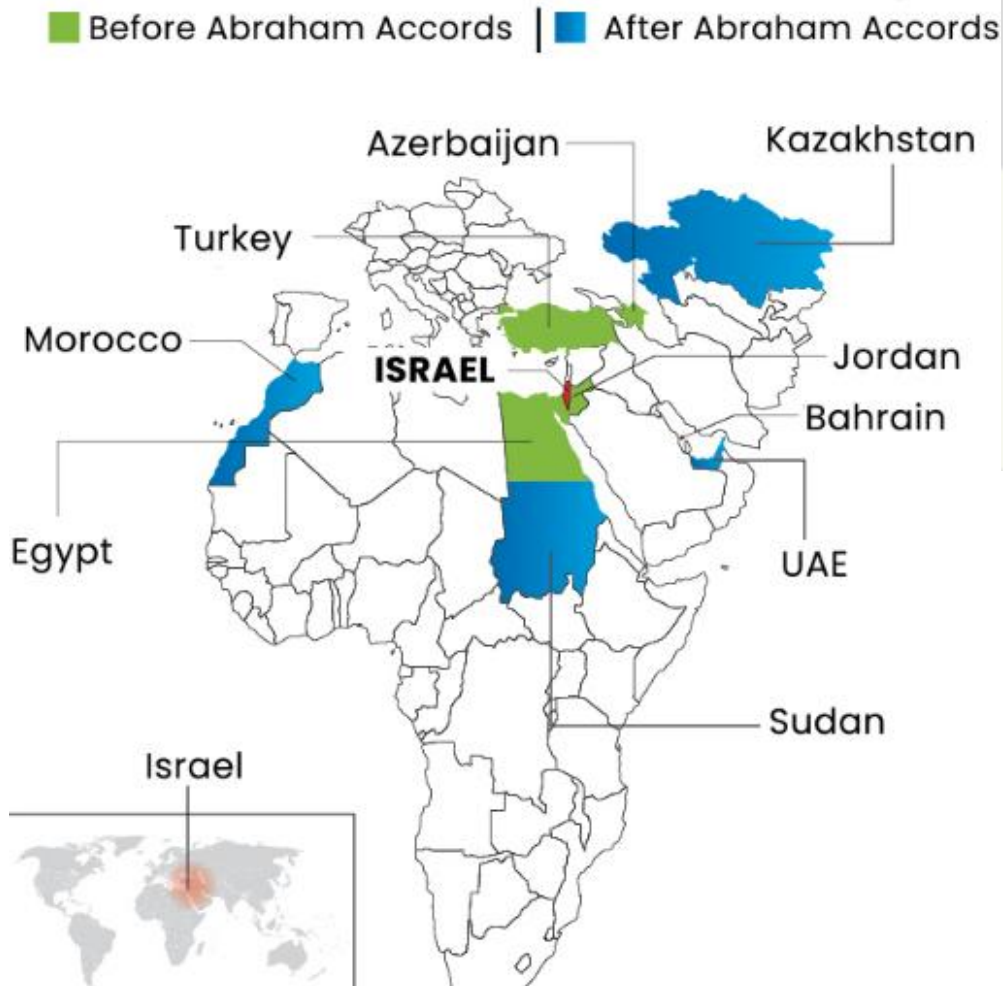
(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वह इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा अब्राहम समझौते में शामिल होने के पक्ष में नहीं हैं।

LIST OF MUSLIM NATIONS RECOGNISING ISRAEL



--:26:--



मुख्य बिन्दु:

अब्राहम समझौता

- अब्राहम समझौते से तात्पर्य 2020 में इज़राइल और कई अरब देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों की एक श्रृंखला से है, जिनकी मध्यस्थता ट्रम्प प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।
- दशकों तक, अधिकांश अरब देशों ने फिलिस्तीनी मुद्दे के हल होने तक इजरायल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
- अब्राहम समझौते ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के पूर्व समाधान के बिना इजरायल और कुछ अरब राज्यों के बीच खुले संबंध स्थापित करके मध्य पूर्व कूटनीति में एक बड़ा बदलाव लाया।
- अब्राहम समझौते के तहत, UAE 2020 में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया।
- **देश:** अमेरिका, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को और कजाकिस्तान।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

लोकायन 26 अभियान

(स्रोत: NEWS ON AIR)

चर्चा में क्यों?

- INS सुदर्शिनी, लोकायन 2026 / लोकायन 26 अभियान के तहत एंटीगुआ और बारबुडा (कैरेबियाई द्वीप) पहुँचा है।

मुख्य बिन्दु:

लोकायन 26 अभियान

- यह 10 महीने की, 22,000 समुद्री मील लम्बा अंतर-महासागरीय अभियान है। इसमें 3 देशों और 18 बंदरगाहों की यात्रा शामिल है।
- इसे जनवरी 2026 में कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान से रवाना किया गया।
- **महत्त्व:** यह वैश्विक महासागरीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करता है और 'महासागर' दृष्टिकोण के अनुरूप है।

INS सुदर्शिनी

- यह INS तरंगिणी के बाद भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी रूप से निर्मित नौकायन प्रशिक्षण पोत है।
- इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसका केंद्र कोच्चि में है।



महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट



वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन 2026-2035 रिपोर्ट

(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन 2026-2035 रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों (2026-2030) के लिए गंभीर वैश्विक तापन और चरम जलवायु दशाओं की चेतावनी दी गई है।



मुख्य बिन्दु:

- **जारीकर्ता:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा। यह रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम के मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा तैयार की जाती है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- 2026-2030 के दौरान वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.3°C से 1.9°C तक अधिक रहेगा।
- 2030 से पहले अस्थायी रूप से 1.5°C की तापवृद्धि सीमा को पार करने की 91% संभावना है।
- आर्कटिक क्षेत्र में सर्दियों का मौसम हाल के ऐतिहासिक औसत की तुलना में औसतन 2.8°C अधिक गर्म होगा।

विश्व मौसम-विज्ञान संगठन (WMO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
- **सदस्य:** 193 सदस्य, जिनमें 187 सदस्य देश और 6 क्षेत्र शामिल हैं।